भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3664

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

उत्तराखंड में शैक्षणिक सुविधाओं का विकास

3664. **श्री अजय भट्टः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार की शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए कोई भावी योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): 'शिक्षा' विषय संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराने और उसमें सुधार करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है। तथापि, केंद्र सरकार उत्तराखंड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा, पीएम श्री और उल्लास जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत उनके द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तत्पश्चात इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन परियोजना अनुमोदन

बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से योजना के कार्यक्रमात्मक और वित्तीय मानदंडों, पूर्व में संस्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

समग्र शिक्षा, प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को कवर करने वाली एक एकीकृत योजना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफ़ारिशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुँच, समतापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा, लैंगिक समता और बेहतर अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना है। विगत तीन वर्षों के दौरान, उत्तराखंड में शैक्षिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न मध्यवर्तनों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं, चहारदीवारी, विद्युतीकरण आदि सहित स्कूल अवसंरचना का निर्माण और सुदृढ़ीकरण;
- चिह्नित स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षा सुविधाओं की स्थापना;
- निपुण भारत मिशन के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) को सुदृढ़ करना;
- पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और अन्य पात्रता-लाभों का प्रावधान;
- सहायक उपकरणों, चिकित्सीय सेवाओं और संसाधन सहयोग सहित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा हेतु सहायता;
- वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा तक पहुंच में सुधार हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन;
- चिह्नित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को सहयोग प्रदान करना;
- विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु खेल, कला, अनुभवात्मक शिक्षा और अन्य गुणवत्तापूर्ण मध्यवर्तनों को बढ़ावा देना;
- दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण;
- बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना;

- निष्ठा और अन्य मध्यवर्तनों के माध्यम से शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण;
- स्कूल सुरक्षा, स्वच्छता और अन्य गुणवत्ता संवर्धन पहलों आदि में सुधार।

केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के तहत, चयनित मौजूदा सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सुविधाओं को स्तरोन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उन्हें एनईपी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करने के लिए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित किया जा सके। इस योजना के तहत उत्तराखंड के 241 स्कूलों का चयन किया गया है। इसी प्रकार, केंद्र प्रायोजित योजना 'उल्लास' के तहत उत्तराखंड सहित सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के उन गैर-साक्षर वयस्कों को शिक्षित करने का उद्देश्य है, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। एनईपी 2020 के अनुरूप, इसका उद्देश्य सामुदायिक स्वयंसेवा के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता और आजीवन अधिगम को बढ़ावा देना है।

उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया वर्ष-वार व्यय इस प्रकार है-

(रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	**समग्र शिक्षा**	**पीएम श्री**	**उल्लास**
2023-24	68020.08	3149.90	79.82
2024-25	78874.16	6443.12	123.71
2025-26	57339.95	5935.73	197.53

.*****